been made in addition to the funds already released:—

RE 1988-89	Rs. 20 crores
BE 1989-90 (Proposed)	Rs. 30 crores

Foodgrains Production Target for 1989-90

1778. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the targetted foodgrains production during the year 1989-90;

(b) whether Government are likely to achieve the target and if not, the reasons; and

(c) what steps are being taken by the Government to achieve the Foodgrains Production Target?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV) : (a) The target of foodgrains production for the year 1989-90 has been fixed at 175.2 million tonnes.

(b) and (c) The target is realistic and likely to be achieved. A number of thrust programmes including Specia! Foodgrains Production Programme, Special Rice Production Programme iri the Eastern States, National Pulses Development Programme, Assistance to Small and Marginal Farmers, Distribution of Minikits etc. are being implemented with a view to increase production of foodgrains. Besides, steps have been taken for timely and adequate supply of inputs, improved irrigation facilities, and adoption of improved technology. Farmers are provided remunerative prices for various food crops through appropriate support/procurement prices fixed in advance of the sowing season.

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोज़गार के निर्धारित लक्ष्य

1779. **डा॰ अबरार अहमद खान:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने-कितने व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और अब तक वास्तव में कितने व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया है;

(ख) वर्तमान रोज़गार योजनाओं के नाम क्या हैं और देश में पूर्ण बेरोज़गार और अर्ध-बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) देश में रुग्न उद्योगों के कारण बेरोज़गार हो गए श्रमिकों की संख्या कितनी है और सरकार उन्हें रोज़गार प्रदान कराने के लिए क्या उपाय करने पर विचार कर रही है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री राधाकृष्ण मालवीय): (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमान लगाया गया है कि योजनावधि के दौरान 403.6 लाख मानक व्यक्ति वर्षों* का अतिरिक्त रोज़गार सृजित होगा। सातवीं योजना में अब तक की अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर सृजित रोज़गार संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। रोज़गार सृजन के लिए विद्यमान मुख्य योजनाएं हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वः रोज़गार हेतु ग्रामीण युवा प्रशिक्षण योजना, शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को स्वः रोज़गार प्रदान करने की योजना तथा शहरी गरीबों के लिए स्वः रोज़गार कार्यक्रम। सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमान लगाया गया था कि 5 वर्ष तथा ऊपर की आयु के व्यक्तियों में सामान्य स्तर की बेरोज़गारी मार्च, 1985 में 92 लाख थी जिसमें 22.4 लाख ऐसे व्यक्ति शामिल थे जिनके पास अनुपूरक कार्य था।

2. रुग्ण उद्योगों के कारण बेरोज़गार हुए श्रमिकों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। सरकार ने उपयुक्त पुनर्वास पैकेजों के अन्तर्गत रुग्ण/बंद औद्योगिक

* मानक व्यक्ति वर्ष का तात्पर्य वर्ष में 273 दिनों के लिए प्रतिदिन 8 घंटे का कार्य है।